Information in respect of incidents of bank dacoities/robberies in Public Sector Banks during the period 1-1-83 to 30-6-85 and 1-1-85 to 30.6.87 and the amounts involved therein, as reported by R.B.I., is as given below:

1-1-83 to 30-6-85		1-1-85 to 30-6-87	
No. of cases	Amount (Rs.in Lakhs)	No.of cases	Amount (Rs. in Lakhs)
192	313.23	239	1232.27

(Data provisional)

(d) and (e) Bank robberies/dacoities, to a considerable extent, depend on the general security environment in the locality. Banks, however, have been taking steps to improve their security arrangements so as to offer as little inducement as possible to miscreants to rob banks and also to deter them. As this is a continuous process, security measures implemented by public sector banks are being reviewed from time to time and whenever further improvements are considered necessary, requisite guidelines instructions are given to the Banks. Depending on the risk factor involved, steps have been taken to appoint security guards, instal appropriate alarm systems, etc. in branches. Since apprehension of the culprits concerned is the most important deterrent; State Governments/ Union Territory Administrations have also been requested to make all out efforts to arrest the culprits. Further, in order to motivate bank employees, the general public and the police to resist robbers/dacoits, a scheme of rewards has been announced.

अधिकारियों के बीच रोष

3083. **श्री रशीद मासूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सिविल अधिकारियों में इस बात से रोष व्याप्त है कि पदोन्नति वेतन एवं वरीयता के मामले में रक्षा अधिकारियों की तुलना में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सही है कि इन अधिकारियों ने इस संबंध में सरकार को शिकायतें भी भेजी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) भारतीय सर्वेक्षण समूह "ब" सेवा से संबंधित असैनिक अधिकारियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण (इंजीनियर अधिकारियों के कॉप्स से भर्ती) नियमावली, 1950 के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण में उपनियुक्त सेना के अधिकारियों की तुलना में अपनी सेवा परिस्थितियों का उल्लेख किया है। ये प्रार्थना पत्र भारतीय सर्वेक्षण में सेना के अधिकारियों की तुलना में पदोन्नति के अवसरों की कमी, वरिष्ठता वेतन आदि के संबंध में है। इन प्रार्थना-पत्रों की संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा रही है। वैसे भारतीय सर्वेक्षण के 'ब' सेवा समूह के असैनिक अधिकारियों की संस्था ने भी 1950 नियमावली की वैधता को चुनौती देते हुए इस मामले को केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा है। ट्रिब्यूनल ने अभी तक इस मामले पर निर्णय नहीं दिया है।

Appointment of LDCs in Income Tax Office

3084. SHRI M. KADHARSHA:
SHRI F. M. GHAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain candidates were nominated by Staff Selection Commission by the end of